year 1985-86, the loss has been less than that in the previous year. The commissioned capacity of this unit has been expanded after nationalisation. The production of market yarn in 1985-86 was 10.82 lakh kgs. as compared to 5.84 lakh kgs. during 1977-78. The spinning productivity has increased from 531.8 gms. to 64.5 gms. during 1985-86.

(b) During the year 1985-86, about 10.82 lakh kgs. of market yarn was produced by the mill.

(c) A sum of Rs. 297.57 lakhs has so far been spent on renovation/modernisation of Orissa Cotton Mills. In addition, an amount of Rs. 249|60 lakhs has been given to this mill towards reimbursement of cash losses.

News-item captioned 'TULF' Opposes plan to Demarcate limits

90. SHRI D.B. CHANDRA GOWDA:
SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item captioned 'TULF opposes plan to demarcate limits' which appeared in the Indian Express of the 14th October, 1986;

(b) if so, what is the reaction of the Central Government thereto; and

(c) what further efforts Government propose to take to solve the ethnic issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The news-item refers largely to one aspect of a proposed political solution to the ethnic problem in Sri Lanka. Government are examining the matter.

(c) Government are continuing the process of negotiations to help work out a political solution to the ethnic problem in Sri Lanka.

वाणिज्य मंत्रालय में राजभाषा कार्यक्रम का क्रियान्वयन

91. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी सलाहकार समिति ने यह तय किया है कि वर्ष 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम को अवश्य पूरा किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा पिछले 17 वर्षों से इसे पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण ने गत वर्ष अपना कितने प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया और पूरा कार्य हिन्दी में न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या हिन्दी का कार्य देखने के लिए कोई कक्ष स्थापित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) से (ग) संघ की राजभाषा नीति के कार्यन्वयन के लिए 1986-87 वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त हो गया है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसे परिचालित कर दिया गया है। मंत्रालय की हिन्दी कार्यान्वियन समिति कार्यक्रम के कार्यान्वियन की मानीटरिंग कर रही है। हिन्दी के काम को देखने के लिए मंत्रालय में एक सैल कार्य कर रहा है। वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं :—

(1) उन सभी टाइपिस्टों को, जिन्हें अभी तक हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षित नहीं किया गया है, हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम तयार किया गया है। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय में ही एक हिन्दी टाईपिंग प्रशिक्षण यूनिट आरभं किया गया है।

(2) मंत्रालय में हिन्दी आशुलिपिकों के एक पूल की व्यवस्था की गई है ताकि हिन्दी में नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग का डिक्टेशन देने के लिए अधिकारी उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकें।

(3) मंत्रालय में तीन अनुभाग अर्थात् रोकड़-1, रोकड़-2 और स्थापना-4 सभी स्तरों पर अपना कार्य केवल हिन्दी में करने के लिए अभिज्ञात किए गए हैं।

(4) मंत्रालय में प्रत्येक अनुभाग को पांच ऐसी फाइलें अभिज्ञात करने के लिए कहा गया है जिनमें केवल हिन्दी में कार्य किया जा सके।

गत् वर्ष के दौरान मानीटरिंग पद्धति में हिन्दी कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी को अलग से संकलित करने की व्यवस्था नहीं की गई थी। तथापि, कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए गए। विगत में कई कारणों से लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है। जिनमें प्रशिक्षित हिन्दी टाइपिस्टों की कमी और भाषा का प्रयोग करने में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त धारा-प्रवाह का अभाव शामिल है।

स्वरोजगार कार्यक्रम

92. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **वित्त** मंत्री 22 जुलाई, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 288 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विधिवत स्वीकृत बहुत सी अर्जियों को बैंकों द्वारा रद्द कर दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं हुई है;

(ख) गुजरात तथा अन्य राज्यों में इस कार्यक्रम के लक्ष्य की पूर्ति न होने के क्या कारण हैं ; और एक निश्चित समय में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंकों को क्या अनुदेश दिए गए हैं;

(ग) जिन राज्यों में पिछले तीन वर्षों में लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई उनमें आगामी वर्षों के लिए लक्ष्य बढ़ाये न जाने के क्या कारण हैं ; क्या इस नीति में सुधार की कोई आवश्यकता है; और

(घ) क्या सरकार उन बैंकों के कार्यकरण की जांच करने का विचार रखती है जिन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किये हैं ताकि दोषी लोगों को दण्ड दिया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपास का उत्पादन

93. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कपास का राज्य-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इस वर्ष कपास का कैरी-ओवर (पिछला शेष) स्टाक क्या हैं और देश की आवश्यकता से यह स्टाक कितना अधिक है ;

(ग) आवश्यकता से अधिक कपास की कितनी मात्रा का और किस एजंसी के माध्यम से तथा किस-किस देश को निर्यात किया जाएगा ;

(घ) कपास की विभिन्न किस्मों के समर्थन मूल्य की घोषणा पिछली बार कब की गई थी और उनका मूल्य क्या है ;

(ङ) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि इस वर्ष किसानों को कपास के लिए समर्थन मूल्य से जो कम दाम मिल रहा है ; और

(च) किसानों को कपास का लाभप्रद मूल्य देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) रूई का राज्य-वार उत्पादन संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। (नीचे देखिए)